भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2616
18 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत रोज़गार

2616 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में रोज़गार के 55 लाख अवसर सृजित करना है;
(ख) यदि हाँ, तो देश में वर्ष 2020-21 में इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सृजित रोज़गार के अवसरों का, आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन से मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता संबंधी जानकारी, मूल्यवर्धन, रोग प्रबंधन और प्रौद्योगिकी समावेश के माध्यम से मछुआरों की आय में कितनी वृद्धि हुई है; और
(घ) सरकार आंध्र प्रदेश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को किस प्रकार सुगम बना रही है और बढ़ावा दे रही है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के ने विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्तावों को 8871.45 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ 20864.29 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है । पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 57.93 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। पीएमएमएसवाई की शुरुआत से, आंध्र प्रदेश राज्य सहित अनुमानित रोजगार के अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है ।

पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता इनपुट, मूल्य संवर्धन, रोग प्रबंधन, टेकनोलॉजी के समावेश और कौशल उन्नयन में वृद्धि के द्वारा मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करना है । मात्स्यिकी और जल कृषि क्षेत्र में आय और आजीविका सृजन के लिए 7199.13 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है जिसमें 32,052 हेक्टेयर मीठे पानी, खारे पानी, लवणीय पानी और बायोफ्लोक तालाबों के निर्माण, तालाब निर्माण के लिए इनपुट सहायता जैसे एरेटर, 25 ब्रूड बैंक और 895 फिनफिश और स्कैम्पी हैचरी, 128 मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयां, 50 रोग निदान गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं (डीसीस डायग्नोस्टिक क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स) और टेकनोलॉजी को सम्मिलित करने की गतिविधियाँ जैसे 12,081 री-सर्कुलेटरी एक्वाक्ल्चर सिस्टम(आरएएस) टैंक, 4,205 बायो-फ्लोक कल्चर टैंक और 52,058 जलाशय केजों की स्थापना आदि शामिल हैं।

(घ): मत्स्य पालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 2398.73 करोड़ रुपए की लागत वाली मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों स्वीकृति दी, जिसमें राज्य में 16 कोल्ड स्टोरेज, 25 मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयाँ, 1645 पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड-चेन परिवहन का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण/मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एमपीईडीए) ने विगत 5 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के सी फूड प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों को इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीकों के विकास के लिए 23.82 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, एमपीईडीए सी फूड प्रसंस्करणकर्ताओं/निर्यातकों को सी फूड मूल्य संवर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है,तथा आंध्र प्रदेश के निर्यातकों को इन्टरनेशनल सी फूड एगसहिबिशन में सह-प्रदर्शक के रूप में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता मिल सके । एमपीईडीए यूरोपीय आयोग जैसे आयातक देशों द्वारा इस क्षेत्र में उत्पादन और प्रसंस्करण संस्थाओं के इन्सपेक्शन ऑडिट के संचालन की सुविधा भी प्रदान करता है। ऐसे ऑडिट आयातक देशों द्वारा जल कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग की रोकथाम, नियंत्रण और निगरानी, उत्पादन प्रणाली में रोग नियंत्रण तंत्र आदि के लिए देश में लागू प्रणाली का आकलन करने के लिए किए जाते हैं ।

****

अनुबंध- I

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत रोजगार के संबंध में दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2616 के उत्तर में उल्लिखित विवरण। पीएमएमएसवाई के तहत अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित रोजगार अवसर (संख्या में)
1	आंध्र प्रदेश	614320
2	अंडमान और निकोबार	4040
3	अरुणाचल प्रदेश	94306
4	असम	172196
5	बिहार	78772
6	छत्तीसगढ	435556
7	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	20388
8	दिल्ली	484
9	गोवा	24008
10	गुजरात	315016
11	हरयाणा	95132
12	हिमाचल प्रदेश	38908
13	जम्मू और कश्मीर	26364
14	झारखंड	114272
15	कर्नाटक	260392
16	केरल	528308
17	लद्दाख	1872
18	लक्षद्वीप	13992
19	मध्य प्रदेश	225540
20	महाराष्ट्र	306708
21	मणिपुर	27116
22	मेघालय	36668
23	मिजोरम	73244
24	नगालैंड	52996
25	ओडिशा	200596
26	पुदुचेरी	77508
27	पंजाब	27372
28	राजस्थान	6952
29	सिक्किम	12352
30	तमिलनाडु	276496
31	तेलंगाना	1161620
32	त्रिपुरा	142292
33	उत्तर प्रदेश	201552
34	उत्तराखंड	70156
35	पश्चिम बंगाल	56404
	कुल	**5793898**

*****